

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 320/18
(आरसीएमएस संख्या 2018/00462)

निर्णय दिनांक:- 29-3-2022

1. श्यामसुन्दर पुत्र गणेशराम सांखला जाति माली निवासी नत्थूसर बास, बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. भीखाराम पुत्र हड़मानराम जाति कुम्हार निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. चम्पादेवी पत्नी भीखाराम जाति कुम्हार निवासी सुरपुरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. जमालदीन पुत्र अकबर अली जाति मुसलमान निवासी मुस्तफा मस्जिद के पास, पूगल रोड़, बंगलानगर, बीकानेर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 23-03-2018

उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थित:-

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-


1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 23-03-2018 जिसके द्वारा अपीलांट की भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को विधि विरुद्ध तरीके से किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।



2
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 3 एएमआर के मुरब्बा नम्बर 87/18 के किला नम्बर 2 ता 9, 13 ता 18 तादादी 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार से दिनांक 06-10-2020 को कय की गई थी तथा कय की दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि सर्वप्रथम राकेश पुत्र नन्दकुमार जाति पुरोहित हो दिनांक 06-09-207 को बतौर मिडियम पेच आवंटित की गई थी। कालान्तर में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार राकेश कुमार को प्राप्त होने पर उनके पक्ष में खातेदारी सनद संख्या 745/13 जारी की गई तथा वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटि द्वारा उक्त भूमि अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज भी अपीलांट के नाम हो चुका है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 92 दिनांक 01-02-2011 अपीलांट के नाम दर्ज हो चुका है।

उन्होंने आगे कथन किया कि उक्त तमाम कार्यवाही के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति की जाँच किये बिना अपीलांट के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम कर दिया गया। जबकि उक्त आवंटन की दिनांक के दिन वादग्रस्त भूमि अपीलांट का आक्यूपाईड लैण्ड थी जो किसी भी रूप में आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मात्र रेस्पोजेन्ट्स को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से अपीलांट के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को किया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। वादग्रस्त भूमि तमाम रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त नहीं की गई है।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोजेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्ध रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोजेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जाँच किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट्स को कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटन किये जाने के मद्देनजर तमाम कार्यवाही आनन-फानन में की गई है। जिसका अदालत मातहत को कतई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खरीदशुदा व आक्यूपाईड लैण्ड थी। जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में रेस्पोजेन्ट्स को नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को न्यायालय स्तर से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध दिनांक 07-01-2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोजेन्ट्स के पक्ष में विधि सम्मत तरीके से किया गया है। उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात् रेस्पोजेन्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोजेन्ट्स द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त उक्त भूमि का बेचान रेस्पोजेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के पक्ष में जरिये


राजस्व अपील अधिकारी
बोकारन

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है तथा आज दिनांक को उक्त भूमि आईसीआईसीआई बैंक पास बतौर रहन है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के अधिकार उत्पन्न नहीं हुए हैं। अपीलांट वादग्रस्त भूमि से किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार नहीं होने व अपना अधिकार साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-03-2018 के विरुद्ध अपील दिनांक 04-09-2018 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत भूमि चक 3 एएमआर के मुख्या नम्बर 87/18 के किला नम्बर 2 ता 9, 13 ता 18 तादादी 14 बीघा भूमि का आवंटन राकेश पुत्र नन्दकुमार को वर्ष 2007 में बतौर मिडियम पेच किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये सनद संख्या 745/13 प्राप्त होने के उपरान्त उक्त भूमि का बेचान अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06-10-2010 को किया गया। उक्त भूमि कालान्तर में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में बतौर भूमिहीन आवंटित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अदालत मातहात द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) के तहत किया गया है तथा रेस्पोजेन्ट द्वारा भी वादगत भूमि की तमाम राशि खजारा राज में जमा करवाने के उपरान्त उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करते हुए कालान्तर में आराजी जैर का बेचान रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को कर दिया गया। वर्तमान में उक्त भूमि


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

आईसीआईसीआई बैंक पास बतौर रहन है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोजेण्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत अपने-अपने अधिकार बताते हुए वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की संरक्षण की चेष्टा की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह तथ्य जॉच का विषय है कि अदालत मातहत द्वारा एक ही भूमि का दोहरा आवंटन किस आधार पर किया गया है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय पक्षकारों के धारण में रही भूमि की जॉच भी अदालत मातहत द्वारा सही तरीके से नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 को पूर्व में आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि पूर्व में अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर खरीदशुदा भूमि रही है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्सम ही इस तथ्य की जॉच कर ली जाती कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्ध रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियों से बचा जा सकता था। चूंकि प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने आवंटन को वैध मानते हुए मौके पर राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है व अपना-अपना कब्जा बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक आवंटन आदेश की वैधता/वादग्रस्त आराजी के मौके पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, यह तथ्य अदालत मातहत की जॉच का विषय है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों आवंटनों के संबंध में अपीलांट/रेस्पोजेण्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकार्ड की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29/3/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान) 29/3/2022
राजस्व अपीलांत प्रधिकारी
बीकानेर बीकानेर